

## लक्ष्मी विलास बैंक का वित्तीय संकट

### प्रलम्ब के लिये

गैर-नष्पादति परसिंपत्तति, भारतीय रज़िर्व बैंक

### मेन्स के लिये

बैंकगि संकट और उसके कारण, बैंकगि सेक्टर पर महामारी का प्रभाव

## चर्चा में क्यों?

[भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (RBI) ने चेन्नई स्थिति लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दविसीय मोरेटोरियम (Moratorium) लागू किया है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक की दैनिक गतिविधियों पर कुछ प्रतर्बिंध लगा दिये गए हैं। साथ ही भारतीय रज़िर्व बैंक ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के वलिय की योजना का मसौदा भी तैयार किया गया है।

## प्रमुख बदि

- भारतीय रज़िर्व बैंक ने बैंकगि वनियमन अधनियम, 1949 की धारा 45(2) के आधार पर चेन्नई स्थिति लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्यवाही करते हुए कुछ वशिषिट प्रतर्बिंध लागू किये हैं।
- रज़िर्व बैंक द्वारा लागू 30 दविसीय मोरेटोरियम (Moratorium) के अंतर्गत 25,000 रुपए से अधिक राशि की नकिसी को प्रतर्बिंधित कर दिया गया है।

## कारण

- लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्यवाही करते हुए भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने कहा कि यह बैंक वगित तीन वर्षों से लगातार घाटे का सामना कर रहा है, जिससे बैंक का नेट-वर्थ प्रभावति हुआ है।
  - ध्यातव्य है कि लक्ष्मी विकास बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में 112 करोड़ रुपए और दूसरी तमिाही में 397 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।
- इस प्रकार लक्ष्मी विलास बैंक अपने वित्तीय संकट से संबंधति मुद्दों को हल करने हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाने में असमर्थ रहा है। साथ ही इस बैंक को तरलता की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है।
- इसके अलावा बैंक द्वारा दिया गया लगभग एक-चौथाई ऋण, बैड एसेट (Bad Asset) अथवा [गैर-नष्पादति परसिंपत्तति](#) (NPA) के रूप में परविरतति हो चुका है।
  - ऑकड़ों के अनुसार, जून 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक की सकल गैर-नष्पादति परसिंपत्ततियों (NPAs) कुल ऋण का 25.4 प्रतर्शित हो गई थी, जो कि जून 2019 में 17.3 प्रतर्शित थी।
- रज़िर्व बैंक की मानें तो बीते कुछ वर्षों में शासन संबंधी गंभीर मुद्दों के कारण लक्ष्मी विलास बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में काफी गरिवट आई है।

## वलिय का प्रस्ताव

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने डीबीएस बैंक लिमिटेड (DBS Bank Ltd) की सहायक/अनुषंगी कंपनी डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India) के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के वलिय के प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया है।
- रज़िर्व बैंक के अनुसार, डीबीएस बैंक इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक के वलिय के पश्चात् दोनों बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी।
- वलिय के बाद दोनों बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 12.51 प्रतर्शित पर पहुँच जाएगा, जो कि वर्तमान में केवल 0.17 प्रतर्शित (लक्ष्मी विलास बैंक) है।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिससे बैंक के जोखिम-भारति क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतर्शित के

रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे पूंजी-से-जोखमि भारति संपत्ति अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है।

- रज़िर्व बैंक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बैंकों के जमाकर्त्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और रज़िर्व बैंक उनके हितों की पूर्ण रक्षा करेगा।
  - ज्ञात हो कि किसी भी अनश्चितता की स्थिति में छोटे जमाकर्त्ताओं के लिये डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) भी एक विकल्प हो सकता है, जो कि रज़िर्व बैंक की एक सहायक/अनुषंगी कंपनी है और छोटे जमाकर्त्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है।

## भारत के वित्तीय सेक्टर का संकट

- वर्ष 2018 में IL&FS के डफॉल्ट हो जाने के बाद से भारत के वित्तीय सेक्टर में ऐसी कई सारी घटनाएँ देखी गईं जहाँ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाएँ अपनी वित्तीय स्थिति किमज़ोर हो जाने अथवा तरलता की कमी के कारण डफॉल्ट हो गईं।
- बीते वर्ष सितंबर माह में 'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक' (PMC) में ऋण घोटाले के कारण बैंकिंग संकट देखने को मिला था, जिसमें एचडीआईएल (HDIL) कंपनी के प्रवर्तक भी शामिल थे, इस घोटाले की जाँच अभी भी जारी है और बैंक के पुनरुत्थान को लेकर कई प्रयास किये जा रहे हैं।
- इसी वर्ष मार्च माह में भारत में नज़ि क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक 'यस बैंक' (Yes Bank) भी संकट का सामना कर रहा था, जिससे नविशकों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था।
- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) भारत के कई पुरानी पीढ़ी के नज़ि बैंकों और बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन की नगिरानी कर रहा है।

## कारण

- गैर-नष्पादति परसंपत्तियों (NPAs) की बढ़ती मात्रा, खराब वित्तीय स्थिति, ऋण से संबंधित घोटाले और शासन से संबंधित मुद्दों आदि ने भारत के बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में एक गंभीर संकट को जन्म दिया है।
  - इसके अलावा तमाम तरह की ऋण गारंटी योजनाओं के बावजूद, ऋण की दर में काफी कम वृद्धि देखने को मिली है, भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2020 में खुदरा ऋणों की वृद्धि दर केवल 10.6 प्रतिशत रही थी।
  - इसके कारण भारतीय बैंकों की आय में कमी आ रही है और वित्तीय संकट का सामना करने हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाना उनके लिये काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - यही कारण है कि बीते 15 महीनों में भारत के नज़ि क्षेत्र के कुछ प्रमुख बैंक और कुछ सहकारी बैंक वित्तीय संकट की चपेट में आ गए हैं।

## महामारी और बैंकिंग सेक्टर

- महामारी के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियाँ और भी गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से आम लोगों और कंपनियों की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण आने वाले समय में बैंकों की गैर-नष्पादति परसंपत्ति (NPA) में और अधिक वृद्धि देखने को मलि सकती है।
- हालाँकि कई विश्लेषकों का अनुमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फार्मास्यूटिकल्स, FMCG और रसायन जैसे क्षेत्रों में बैंकों का NPA काफी कम रहेगा, कति आतथिय, पर्यटन और वमिानन क्षेत्र में बैंकों के NPA में वृद्धि देखने को मलिंगी।

## आगे की राह

- बैंकिंग सेक्टर के अधिकांश विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि जब भी भारत की बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं ने वित्तीय संकट का सामना किया है तो रज़िर्व बैंक ने उन्हें इस संकट से उबारने में सक्रिय भूमिका अदा की है।
- भारत के वित्तीय सेक्टर को गंभीर संकट से बचाने के लिये किसी भी प्रकार के अल्पकालिक उपाय के साथ-साथ दीर्घकालिक उपायों की भी आवश्यकता है, नीति निर्माताओं को बैंकिंग संकट के मूल कारणों पर विचार करते हुए उसे दूर करने के प्रयास करना चाहिये।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस